



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 23 दिसम्बर, 2002/2 पौष, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 दिसम्बर, 2002

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-22/2002-लैज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-12-2002 को

3241-राजपत्र/2002-23-12-2002—1,438.

(2779)

मूल्य : 1 रुपया ।

प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

2002 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अध्यादेश, 2002

भारत राज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के गठन और हिमाचल प्रदेश राज्य में आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति तथा इसकी समस्त शाखाओं में व्यवसाय में विनियुक्त चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर के रख-रखाव तथा तत्सम्बन्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड 1 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं।

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अध्यादेश, 2002 है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस अध्यादेश के शेष उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

परिभाषाएं।

(क) “नियत दिन” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसको कि धारा 1 से भिन्न, इस अध्यादेश के उपबन्ध, धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन प्रवृत्त होंगे;

(ख) “आकस्मिक रिक्ति” से, किसी कार्यालय में निर्वाचन या नामांकन द्वारा भरे गये किसी पद की अवधि समाप्त होने के कारण रिक्त होने वाले पद के अन्यथा, होने वाली रिक्ति अभिप्रेत है;

(ग) “परिषद्” से, इस अध्यादेश की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) “कार्यकारी समिति” से, इस अध्यादेश की धारा 11 के अधीन गठित परिषद् की कार्यकारी समिति अभिप्रेत है;

(ङ) “सरकार” से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(च) “चिकित्सा व्यवसायी” या “व्यवसायी” से आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली और इसकी सभी शाखाओं में व्यवसाय करने में लगा हुआ ऐसा

कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में विहित अर्हता रखता है ;

- (छ) "चिकित्सा (मैडीसिन)" से, आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शल्य चिकित्सा तथा प्रसूति विज्ञान भी है परन्तु पशु चिकित्सा या पशु शल्य चिकित्सा या होम्योपैथी या आयुर्वेद या सिद्ध या यूनानी चिकित्सा प्रणाली इसके अन्तर्गत नहीं है और पद चिकित्सा (मैडीसिन) का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा ;
- (ज) "सदस्य" से, परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;
- (झ) "राजपत्र" से, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (ङ) "विहित" से, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (ट) "अध्यक्ष" से, परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ठ) "उपाध्यक्ष" से, परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ड) "रजिस्टरर" से, इस अध्यादेश के अधीन तैयार या तैयार किया समझा गया या अनुरक्षित चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;
- (ढ) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी" से, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में यथा विहित अपेक्षित अर्हता रखने वाला कोई चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, और जिसका नाम तत्समय रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो परन्तु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसका नाम अस्थायी रूप से रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है ; और
- (ण) "रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार" से, इस अध्यादेश की धारा 14 के अधीन नियुक्त यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ।

अध्याय-2

परिषद् की स्थापना

परिषद् का गठन और परिचालन । 3. (1) ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए एक परिषद् का गठन किया जाएगा जिसे "हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्" कहा जाएगा ।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने तथा इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त कार्य करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :—

- (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में यथा विहित अपेक्षित अर्हता रखने वाले सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले चार सदस्य ;

(ख) हिमाचल प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित चिकित्सा संकाय रखने वाले प्रत्येक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से, चिकित्सा संकाय के सदस्यों द्वारा इस विद्यालय के अध्यापन संकाय के स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित एक-एक सदस्य ;

(ग) हिमाचल प्रदेश चिकित्सा संघ द्वारा निर्वाचित एक सदस्य सहित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले नौ सदस्य :

परन्तु कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी (प्रत्याशी) के रूप में तब तक खड़ा होने या मतदान करने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि—

1. वह भारत का नागरिक न हो ;
2. वह हिमाचल प्रदेश में न रहता हो या वहां अपना कारोबार न करता हो या यहां कार्यरत न हो ;

(घ) पदेन सदस्य के रूप में हिमाचल प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय का प्राधानाचार्य और

(ङ) पदेन सदस्य के रूप में , निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश ।

(4) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे ।

(5) सदस्यों तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसे स्थान और ऐसी रीति में होगा, जैसी कि विहित की जा सकेगी ।

(6) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचक अपेक्षित संख्या में सदस्यों का या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो सरकार, जैसा यह उचित समझे रिक्त या रिक्तियां भरने के लिए अपने-अपने प्रवर्ग के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने वाले अहित व्यक्तियों में से सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकती है, और इस धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति रिक्तियों के नियमित आधार पर भरे जाने के समय तक निर्वाचित मान लिये जायेंगे ।

(7) जहां किसी निर्वाचन में किसी सदस्य या अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सरकार के पास भेज दिया जाएगा और सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(8) उप-धारा (3) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी,—

(क) इस अध्यादेश के अधीन पहली बार परिषद् के गठन की बाबत बारे में इसके सदस्य अपने-अपने प्रवर्ग के सदस्यों के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अहित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ; और

(ख) इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्य कुल मिलाकर तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, जैसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(9) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सदस्यों के नाम प्रकाशित करेगी।

अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष
और
सदस्यों का
कार्यकाल।

4. (1) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सदस्य इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (9) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा :

परन्तु किसी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सा संकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति या कोई पदेन सदस्य, सदस्य के रूप में पद पर बना नहीं रहेगा यदि वह उस संकाय के सदस्य के रूप में सम्बद्ध नहीं रहता है या, यथास्थिति, अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व ऐसे पद पर बना नहीं रहता है।

(2) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने निर्वाचन की तारीख से अपने पद पर बना रहेगा जिसको कि सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल का अवसान हो जाता है।

(3) पद छोड़ने वाले सदस्य का कार्यकाल, उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख के आगामी दिन से बढ़ाए जाने तथा समाप्त किए जाने के लिए समझा जाएगा जिस दिन अध्यादेश की धारा 3 की उप-धारा (9) के अधीन नए सदस्यों का नाम प्रकाशित किया गया हो।

(4) पद छोड़ने वाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख से तुरन्त पूर्व बढ़ाए जाने या समाप्त किए जाने के लिए समझा जाएगा, जिस तारीख से यथास्थिति, उत्तराधिकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ हो।

(5) पद छोड़ने वाला सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष एक और क्रमवर्ती अवधि के लिए, निर्वाचन और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) परिषद् द्वारा किसी भी सदस्य को 6 माह से अधिक अवधि के लिए अनु-पस्थिति की इजाजत नहीं दी जाएगी।

आकस्मिक
रिक्तियां।

5. (1) धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा :

परन्तु यह कि किसी निर्वाचित सदस्य के कार्यालय में ऐसी कोई रिक्ति जो समस्त सदस्यों के पद की अवधि के अवसान की तारीख से छः मास के भीतर हो जाती है, तो वह भरी नहीं जाएगी।

(2) धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन या उप-धारा (8) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा तत्काल सरकार को दी जाएगी तथा उसके पश्चात् यथासम्भव सरकार द्वारा नामनिर्देशन द्वारा उसे भरा जाएगा।

(3) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचित या उप-धारा (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति इस अध्यादेश की धारा 3 या 4 की उप-धारा (8) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, केवल उसी समय तक पद पर रहेगा जब तक वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह, यथास्थिति, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया है पद पर रहता, यदि रिक्ति न हुई होती।

6. (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी भी समय परिषद् को सम्बोधित, तथा रजिस्ट्रार को परिदत्त लिखित नोटिस द्वारा त्याग-पत्र दे सकेगा और त्याग-पत्र उसी तारीख से, जिसको वह परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया है, या नोटिस के परिदान की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर है, प्रभावी होगा। त्याग-पत्र।

(2) कोई भी निर्वाचित सदस्य, किसी भी समय अध्यक्ष को सम्बोधित लिखित में नोटिस द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा और नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी भी समय सरकार को लिखित में संबोधित और रजिस्ट्रार को परिदत्त नोटिस द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा। ऐसा प्रत्येक त्याग-पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह यथास्थिति, अध्यक्ष या सरकार द्वारा, स्वीकृत किया जाता है या 60 दिनों की समाप्ति पर जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

7. (1) कोई भी सदस्य चुने जाने या नामनिर्दिष्ट किये जाने या निरन्तर सदस्य बने रहने के लिए निरहित होगा,— निरहताएं।

- (क) यदि वह अनन्योचित दिवालिया है ; या
- (ख) यदि वह विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है ; या
- (ग) यदि रजिस्ट्रार से उसका नाम हटा दिया गया हो और पुनः उसमें दर्ज नहीं किया गया हो ; या
- (घ) यदि वह परिषद् का पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी हो ; या
- (ङ) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्गस्त है।

(2) यदि कोई सदस्य धारा 4 की उप-धारा (7) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमत परिषद् की इजाजत के बिना या ऐसे कारणों के बिना, जो परिषद् की राय में पर्याप्त हो, परिषद् की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो परिषद् उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी और रिक्ति को भरने के लिए पग उठा सकेगी।

(3) यदि कोई सदस्य उप-धारा (1) में वर्णित किसी निरहता के अध्याधीन हो जाता है या पाया जाता है तो परिषद् सरकार को इसकी रिपोर्ट देगी और यदि सरकार उसकी निरहताओं के बारे में संतुष्ट हो जाती है तो, वह उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी।

8. (1) परिषद् की बैठकें ऐसी रीति से बुलाई और संचालित की जाएंगी जैसी कि विहित की जाए। परिषद् की बैठक।

(2) अध्यक्ष जब उपस्थित हो, परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों में से चुना गया कोई अन्य सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद् की बैठक के सभी मामलों का सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

(4) बैठक के पीठासीन प्राधिकारी को, मतों की समानता की स्थिति में, दूसरा और निर्णायक मत प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(5) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित आठ सदस्यों से गणपूर्ति की जाएगी। जब गणपूर्ति अपेक्षित हो तथा वह न हो तो पीठासीन प्राधिकारी ऐसी गणपूर्ति के लिए, तीस मिनट से अन्यून के लिए इंतजार करके बैठक को ऐसे समय या किसी और दिन के लिए, जिसे परिषद् के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर अधिसूचित किया जाए, स्थगित करेगा तथा कारबार जिसे मूल बैठक में लाया जाना था उसे स्थगित बैठक में लाया जाएगा तथा गणपूर्ति हो या न हो, उसे उस बैठक या पश्चात्पूर्ति स्थगित बैठक में निपटाया जाएगा।

बैठकों की कार्यवाहियां तथा कार्यों की विधि-मान्यता।

9. (1) परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को गोपनीय रखा जाएगा, तथा कोई भी व्यक्ति परिषद् के पूर्व संकल्प के बिना उसके किसी भाग को प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा में कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को परिषद् द्वारा स्वीकृत किसी संकल्प के पाठ को प्रकट या प्रकाशित करने से प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी जब तक कि परिषद् ऐसे संकल्प को गोपनीय रखे जाने का निर्देश नहीं देती।

(2) किसी बैठक में किसी व्यक्ति को, सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट करने में कोई निरर्हरता या वृद्धि; परिषद् के किसी कार्य या कार्यवाहियों को, जिसमें ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया हो, निष्फल करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि अधिकांश सदस्य जिन्होंने ऐसे कार्य या कार्यवाहियों में भाग लिया हो, मत देने के हकदार थे।

(3) परिषद् में किसी रिक्ति के दौरान कार्यरत अन्य सदस्य इस प्रकार कार्य कर सकते हैं मानों कोई रिक्ति हुई ही न थी।

(4) परिषद् द्वारा किया गया कोई कार्य केवल किसी रिक्ति के आधार पर या परिषद् के गठन में किसी के कारण प्रश्नगत नहीं होगा।

परिषद् की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य।

10. ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी इस अध्यादेश के उपबन्धों के द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए परिषद् की शक्तियां कर्तव्य और कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(क) चालू रजिस्टर का रख-रखाव और चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करना ;

(ख) रजिस्ट्रार के किसी निर्णय के विरुद्ध अपीलों को सूचना और निर्णय करना ;

(ग) व्यवसायियों के वृत्तिक आचरण को विनियमित करने के लिए आचार संहिता विहित करना ;

- (घ) किसी व्यवसायी की भर्त्सना करना या उसे निलंबित करना या रजिस्टर से उसका नाम हटाना या उसके विरुद्ध अन्य ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, जो कि परिषद् के विचार से आवश्यक या समीचीन हो ;
- (ङ) चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दुर्य्यवहार या लापरवाही करने पर जनता; रोगियों और उनके रिश्तेदारों सहित से शिकायत प्राप्त करना, उन्हें जांच के लिए आगे भेजना तथा मामले की वरीयता के आधार पर, उस पर निर्णय लेना तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या प्रतिकर देना तथा इसी तरह तुच्छ सारहीन शिकायतों के विरुद्ध कार्यवाही करना ;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अनर्हित व्यक्ति औषधियों की वैज्ञानिक प्रणाली का व्यवसाय न कर रहा हो ;
- (छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना तथा ऐसे अन्य सभी कार्य करना जैसे विहित किए जाएं ; और
- (ज) व्यवसायिक कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे अपने सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना ।

11. (1) परिषद्, यथाशीघ्र पदेन सदस्य के रूप में अध्यक्ष और परिषद् द्वारा अपने सदस्य में से निर्वाचित सदस्यों की ऐसी संख्या, जैसी विहित की जाएं, से गठित एक कार्यकारी समिति गठित करेगी ।

कार्यकारी समिति ।

(2) पद की अवधि और आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, ऐसी होगी जैसी विहित की जाए ।

(3) इस अध्यादेश द्वारा प्रदत्त, अवधारित तथा सौंपी गई ऐसी शक्तियों, कर्त्तव्यों और कार्यों के अतिरिक्त कार्यकारी समिति, परिषद् की ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कर्त्तव्यों का अनुपालन तथा कृत्यों का निष्पादन करेगी, जैसे कि परिषद् द्वारा इसे समय-समय पर, सौंपे जाएं ।

(4) अध्यक्ष कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।

12. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे जैसे विहित किए जाएं ।

परिषद् और कार्यकारी समिति के सदस्यों के देय भत्ते ।

13. (1) परिषद् की आय निम्न प्रकार होगी :—

परिषद् की आय एवं व्यय ।

- (क) व्यवसायियों से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण फीस या
- (ख) सरकार से प्राप्त अनुदान यदि कोई हो ; और
- (ग) परिषद् द्वारा ली गई (समुत्थापित) कोई अन्य राशि ।

(2) परिषद् निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए व्यय उपगत करने में सक्षम होगी :—

- (क) रजिस्ट्रार तथा परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारों वृन्द का वेतन और भत्ते ;

- (ख) परिषद् तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को संदत्त किया जाने वाला यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते ;
- (ग) असेसर (कर निर्धारकों) को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक ; और
- (घ) ऐसे अन्य व्यय जो इस अध्यादेश के अधीन कर्तव्यों के अनुपालन तथा कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की अनुसूची I, II तथा III में यथाविहित अहित चिकित्सा स्नातक होंगे । (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 102)

- (2) कार्यकारी समिति रजिस्ट्रार को अवकाश स्वीकृत कर सकेगी :

उनके कर्तव्य और कृत्य ।

परन्तु यदि अवकाश की अवधि एक माह से अधिक न हो, तो अवकाश अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(3) रजिस्ट्रार के कार्यालय में अवकाश, या किसी अन्य कारण से अस्थायी रिक्ति के दौरान उप-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा । रजिस्ट्रार एवं उप-रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति सरकार की पूर्व मंजूरी से उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार समझा जाएगा :

परन्तु यह कि जब ऐसी रिक्ति की अवधि एक मास से अधिक न हो तो नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी जो ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कार्यकारी समिति तथा सरकार को तुरन्त देगा ।

(4) परिषद् सरकार की पूर्व मंजूरी से रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को निलंबित, पदच्युत तथा हटा सकेगी या ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, उस पर अन्य शास्ति अधिरोपित कर सकेगी ।

(5) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय रजिस्ट्रार के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं ।

(6) रजिस्ट्रार, परिषद् का सचिव तथा कार्यकारी अधिकारी और वह परिषद् और उसकी कार्यकारी समिति की सभी बैठकों में उपस्थित होगा तथा वह बैठकों के कार्यवृत्त और उपस्थित सदस्यों के नाम और ऐसी बैठकों की कार्यवाही रखेगा ।

(7) परिषद् के लेखे रजिस्ट्रार द्वारा विहित रीति में रखे जाएंगे ।

(8) रजिस्ट्रार के पास कर्मचारी वृन्द पर निगरानी रखने के लिए ऐसी पर्यवेक्षणीय शक्तियां होंगी जैसी विहित की जाएं और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसे विहित किया जाए ।

(9) रजिस्ट्रार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

अध्याय-3

रजिस्टर तैयार करना तथा उसका रख-रखाव

15. (1) नियत दिन के पश्चात् यथाशीघ्र रजिस्ट्रार, इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लिए चिकित्सा व्यवसायियों का एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका रख-रखाव करेगा।

रजिस्टर तैयार करना।

(2) रजिस्टर ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसे भागों में विभाजित किया जा सकेगा जैसा विहित किया जाए। रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा नाम, पता तथा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के नाम सहित अर्हता, अर्हता प्राप्त करने की तारीख और ऐसी अन्य विवरणियां होंगी, जैसी विहित की जाए।

(1956 का 102) (3) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की अनुसूची I, II तथा III में विनिर्दिष्ट कोई भी अर्हता रखता हो, तथा जिसने भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के द्वारा या अधीन उल्लिखित किन्हीं शर्तों के अधीन किसी भी समय विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार को आवेदन किया हो तथा विहित फीस का संदाय किया हो तथा अपनी रजिस्ट्रीकृत अर्हता, के सबूत प्रस्तुत किये हों, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने का हकदार होगा।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम 1 मई, 1961 से पहले भारतीय चिकित्सा परिषद् के रजिस्टर में दर्ज था तथा नियत दिन से तुरन्त पूर्व के दिन तक जिसका नाम रजिस्टर में हों, वह इस अध्यादेश के अधीन तैयार किए गए रजिस्टर में अपने नाम बनाए रखने का हकदार होगा।

(5) नियत दिन से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसी आगामी अवधि, जिसे सरकार अनुदत्त करे रजिस्ट्रार राजपत्र और परिषद् द्वारा चयनित समाचार-पत्रों में ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, सामान्य नोटिस प्रकाशित करेगा जिसके माध्यम से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिस पर उप-धारा (4) लागू होती है, यदि वह इस अध्यादेश के अधीन रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने का इच्छुक है, रजिस्ट्रार को विहित रीति में विहित शुल्क देने को कहा जाएगा तथा ऐसे ही प्रयोजन के लिए वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, उसके अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा व्यक्तिगत नोटिस भेजेगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सामान्य नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी फीस का संदाय कर देता है तो उसका नाम रजिस्टर में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन विहित फीस के संदाय की अन्तिम तारीख के अवसान के पश्चात् तथा पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुरूप तैयार किये गए रजिस्टर के तैयार होने के पश्चात् रजिस्ट्रार राजपत्र तथा परिषद् द्वारा चयनित समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा कि रजिस्टर तैयार कर लिया गया है तथा रजिस्टर राजपत्र में ऐसे नोटिस के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति चाहे वह चिकित्सा की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति में अर्हित हो, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के बिना हिमाचल प्रदेश राज्य में व्यवसाय नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति में

सेवारत है या व्यवसाय कर रहा है, इस अध्यादेश [के अधीन परिषद् में रजिस्ट्रीकृत होगा।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अपने व्यवसाय के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा और यदि ऐसे भाग एक से अधिक हों तो वह इसे इनमें से किसी भी भाग में प्रदर्शित करेगा, ऐसा रजिस्ट्रीकरण 3 वर्ष की अवधि के लिए विधिमाम्य होगा।

(9) कोई भी व्यक्ति जो, उप-धारा (7) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है दोषसिद्धी पर, जुर्माने से दण्डित होगा जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।

कतिपय
मामलों में
रजिस्ट्री-
करण के
लिए विशेष
प्रक्रिया।

16. (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत की सीमा के बाहर किसी भी स्थान के किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हता रखता हो (भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की दूसरी अथवा तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्हता से अन्यथा) इस अध्यादेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण न कर लिया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई चिकित्सा अर्हता हो, वह अपनी अर्हता के सही-सही विवरण के साथ डिग्री डिपलोमा, अनुज्ञापत्र अथवा प्रमाण-पत्र भेजकर परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। परिषद् इसको भारतीय चिकित्सा परिषद् के पास उनकी राय के लिये भेज देगी और उनकी राय के अनुसार कार्य करेगी,

व्यक्ति जो
रजिस्ट्रीकृत
नहीं हो
सकते।

17. इस अध्यादेश के धारा 15 और 16 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम, नियत दिन से पूर्व या पश्चात् इस अध्यादेश अथवा चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन रखे किसी रजिस्टर से, वृत्तिक कदाचार के आधार पर हटा दिया गया है, रजिस्टर में अपने नाम की प्रविष्टि का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि जिस रजिस्टर से उसका नाम हटाया गया है, उसमें उसका नाम पुनः प्रत्यावर्तित करने का सम्यक् रूप से आदेश न कर दिया हो।

अस्थाई
रजिस्ट्रीकरण
के लिए

18. (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत होने का इच्छुक है तो वह रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा तथा विहित फीस संदत्त करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके नाम उप-धारा (1) के अन्तर्गत रजिस्टर में प्रविष्टि है, को विहित प्ररूप में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा और ऐसा प्रमाण-पत्र उसमें यथाविनिर्दिष्ट अवधि तक मान्य होगा।

रजिस्टर
का रख-
रखाव।

19. (1) रजिस्ट्रार का, रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज करना और इस अध्यादेश के उपबन्धों और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना, कर्तव्य होगा।

(2) प्रत्येक जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार, अध्यादेश के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल इस अध्यादेश के अन्तर्गत नियुक्त किए गए

रजिस्ट्रार को, अपने हस्ताक्षर से जारी ऐसी मृत्यु के समय व स्थान के विवरण सहित डाक द्वारा एक प्रमाण-पत्र भेजेगा तथा ऐसे प्रमाण-पत्र की लागत तथा पत्र व्यवहार में आए कार्यालय व्यय को भी वसूल करेगा ।

(3) उन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के नाम, जिनकी मृत्यु हो जाती है या जिनके नामों को इस अध्यादेश की धारा 22 के अधीन रजिस्टर से हटाए जाने का निदेश दिया गया है, रजिस्टर से हटा दिए जाएंगे ।

(4) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है और वह रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् रजिस्टर के रिकार्ड में अपने नाम में कोई परिवर्तन कराने का इच्छुक है, वह इस निमित्त किए गए आवेदन पर तथा विहित फीस के संदाय पर रजिस्टर में अभिलिखित अपने नाम में ऐसा परिवर्तन कराने का पात्र होगा ।

(5) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 26 के उपबन्धों के अधीन कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, और जो रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करता है वह इस निमित्त किये गये आवेदन पर और विहित फीस के संदाय पर, रजिस्टर में अपने नाम के समक्ष ऐसी अतिरिक्त अर्हता दर्ज कराने का हकदार होगा ।

(1956
का केन्द्रिय
अधिनियम
संख्यांक
102)

(6) जहां रजिस्ट्रार के समाधान में यह दर्शित किया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है तो रजिस्ट्रार, विहित फीस की अदायगी पर तथा क्षतिपूर्ति बांड देने पर कार्यकारी समिति की पुष्टि और अनुमोदन के पश्चात् एक डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करेगा ,

20. (1) इस अध्यादेश की धारा 15 की उप-धारा (6) के अधीन सूचना के प्रकाशन के पश्चात् ऐसे समय पर, जैसा कि परिषद् उचित समझे और उसके प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार उस समय तक रजिस्टर में दर्ज सभी व्यक्तियों के नामों की एक सही/शुद्ध सूची मुद्रित और प्रकाशित करेगा परन्तु निर्वाचन की प्रक्रिया के आरम्भ होने के तीन माह के पश्चात् ऐसी सूची प्रकाशित नहीं करायी जाएगी ।

रजिस्ट्रीकृत
व्यवसायियों
की सूची का
प्रकाशन ।

(2) रजिस्ट्रार वार्षिक रूप से कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित की गई सूची का निम्नलिखित को दर्शाते हुए संलग्न (एडेंडम) एवं शुद्धि-पत्र मुद्रित एवं प्रकाशित करायेंगे :--

- (क) रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट या पुनःप्रविष्ट परन्तु पहले से ही मुद्रित प्रकाशित किसी सहायक सूची में शामिल न किए गए सभी व्यक्तियों के नाम;
- (ख) किसी भी सहायक सूची में शामिल उन सभी व्यवसायियों के नाम, जिनके नाम किसी भी कारण से रजिस्टर में से हटा दिए गए हों, और पुनः प्रविष्ट नहीं किए गए हों ; तथा
- (ग) सहायक सूची में कोई अन्य संशोधन ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित सूची का प्ररूप उसमें शामिल किए जाने वाले विवरण तथा इसके प्रकाशन की रीति वैसी होगी जैसी कि विहित की जा सकेगी ।

(4) उप-धारा (1) एक में विनिर्दिष्ट सूची की प्रति, सभी न्यायालयों और न्यायिक या न्यायिकल्प कार्यवाहियों में इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है और ऐसी प्रति में किसी व्यक्ति के नाम का न होना साक्ष्य रहेगा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति के मामले में, जिसका नाम ऐसी प्रति में नहीं है, रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से रजिस्टर में उस व्यक्ति की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति इस अध्यादेश के उपबन्धों के अन्तर्गत उस व्यक्ति की प्रविष्टि का प्रमाण होगी।

अनुशासनिक
समिति।

21. एक अनुशासनिक समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (1) परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला अध्यक्ष;
- (2) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य;
- (3) परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला विधि विशेषज्ञ;
- (4) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट इलाके का कोई जनसेवक;
- (5) सुसंगत विशेषज्ञता, जिसके परिवाद संबंधित है, में परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला विख्यात चिकित्सा विशेषज्ञ; और
- (6) हिमाचल प्रदेश चिकित्सा संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य जिसकी कम से कम दस वर्ष की अवस्थिति रही है;

रजिस्टर
से नामों
का हटाया
जाना।

22. (1) यदि परिषद् या कार्यकारी समिति द्वारा विहित रीति में सम्यक् जांच के पश्चात् कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी परिषद् या कार्यकारी समिति द्वारा किसी अवचार के लिए दोषी पाया जाता है, तो परिषद् :—

- (क) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी को चेतावनी पत्र जारी कर सकेगी; या
- (ख) ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी कि—
 - (i) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी का नाम ऐसी अवधि के लिए जो उपर्युक्त निर्देश के विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, रजिस्टर से हटा दिया जाए, या
 - (ii) रजिस्टर से स्थाई रूप से हटा दिया जाए।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अवचार का दोषी समझा जाएगा, यदि

- (क) वह नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है; या
- (ख) परिषद् की राय में चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित, विशेषकर परिषद् या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित किसी नैतिक संहिता के अन्तर्गत उसका आचरण कुत्सित; भण्ड हो।

(2) परिषद्, दर्शाए गए पर्याप्त कारण के आधार पर किसी भी अनुवर्ती तारीख को निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के अन्तर्गत हटाए गए किसी चिकित्सा व्यवसायी का नाम

रजिस्टर में ऐसी शर्तों के आधार पर और ऐसी फीस की मंदाय पर, जसी परिषद् द्वारा विहित की जाए, पुनः प्रविष्ट किया जाएगा।

(3) परिषद् अपने प्रस्ताव पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर उचित जांच के पश्चात् रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि का रद्द कर सकेगी या बदल सकेगी यदि परिषद् के विचार से ऐसी प्रविष्टि धोखा-घड़ी से या गलत तरीके से की गई थी।

(4) इस धारा के अधीन परिषद् या कार्यकारी समिति के पास यथास्थिति, वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों में किसी वाद की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं, अर्थात् :-

- (क) किसी व्यक्ति को हाजिर करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;
- (ख) दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना ; और
- (ग) गवाहों की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करना।

(5) इस धारा के अधीन समस्त जांच, भारतीय दण्डसंहिता, 1860 की धारा 193, 219 तथा 228 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां मानी जाएंगी।

(6) इस धारा के अधीन किसी जांच से उत्पन्न होने वाले किसी विधि के प्रश्न पर यथास्थिति, परिषद् या कार्यकारी समिति को सलाह देने के प्रयोजनार्थ इस प्रकार की समस्त जांच में एक असेसर (कर निर्धारक होगा), जो दस वर्ष से अन्यून अवधि के लिए :-

- (i) एडवोकेट अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत नामांकित एडवोकेट रहा हो या
- (ii) किसी उच्च न्यायालय का कोई एटार्नी रहा हो।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ जिस अवधि में कोई व्यक्ति एडवोकेट के रूप में नामांकित रहा है, उस अवधि की गणना में ऐसी अवधि शामिल होगी, जिसमें वह भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत एडवोकेट के रूप में नामांकित किया गया था।

(7) जहां कोई असेसर (कर निर्धारक) किसी विधि के प्रश्न, प्रक्रिया या किसी अन्य मामले पर, यथास्थिति, परिषद् या कार्यकारी समिति को, परामर्श देता है, वह ऐसा परामर्श, जांच से संबंधित उपस्थित प्रत्येक पक्षकार या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में देगा या यदि ऐसा परामर्श परिषद् या कार्यकारी समिति द्वारा अपने निष्कर्षों को सुनाया जाना शुरू करने के पश्चात् दिया जाता है तो यथापूर्वोक्त किसी ऐसे प्रश्न पर परिषद् या कार्यकारी समिति असेसर (कर-निर्धारक) के परामर्श को स्वीकार नहीं करती है। तो ऐसे पक्षकार या व्यक्ति को भी सूचित किया जाएगा।

(8) इस धारा के अन्तर्गत कोई असेसर (कर-निर्धारक) या तो साधारणतः या किसी विशेष जांच में नियुक्त किया जा सकेगा और उसे विहित पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा।

23. (1) इस अध्यादेश की धारा 15 और 20 में किसी बात के होते हुए भी धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन नोटिस के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् ऐसी तारीख को, जिसका विनिश्चय कार्यकारी समिति सरकार की मंजूरी से करें, और तत्पश्चात् प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् रजिस्ट्रार विहित प्ररूप में राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित करवाएगा जिसके द्वारा सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों से, नोटिस के प्रकाशन से 45 दिन की अवधि के भीतर, अनुमोदित चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के ऐसे साध्य सहित, जैसा विहित किया जाए,

रजिस्ट्री-
करण का
नवीकरण।

अपने-अपने नामों को रजिस्टर में सतत् बनाए रखने हेतु, रजिस्ट्रार को आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन आवेदन विहित अवधि में नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार व्यक्ति/क्रमी का नाम रजिस्टर से हटा देगा और रजिस्ट्रीकृत डाक से उसे इस प्रकार हटाए जाने की सूचना देगा :

परन्तु यदि इस प्रकार हटाए गए नाम को जारी रखने के लिए कोई आवेदन, रजिस्ट्रार से नाम को हटाए जाने की तारीख के छः मास के भीतर, किया जाता है तो इस प्रकार हटाया गया नाम रजिस्ट्रार पर दोबारा विहित फीस जमा कराने पर पुनः प्रविष्ट किया जाएगा।

अपीलें।

24. (1) इस अध्यादेश के अधीन रजिस्ट्रार के किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति जिस तारीख को उसे निर्णय से सूचित किया गया है उस तारीख से तीस दिनों के भीतर, परिषद् को अपील कर सकेगा जो विहित रीति में अपील की सुनवाई करेगी और विनिश्चय करेगी।

(2) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में यथा उपबन्धित के सिवाए, इस अध्यादेश के अधीन परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

रजिस्ट्रीकृत
चिकित्सा
व्यवसायी के
अधिकार।

25. तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(i) पद “वधितः अर्हित चिकित्सा व्यवसायी” या “सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी” या किसी व्यक्ति को चिकित्सा व्यवसायी के रूप में या चिकित्सा व्यवसाय के सदस्य के रूप में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त अभिव्यक्त करने वाले किसी शब्द में, हिमाचल प्रदेश के सभी अधिनियमों और (हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू) समस्त केन्द्रिय अधिनियमों में प्रयुक्त होने पर, जहां तक कि ऐसे अधिनियम किसी ऐसे मामले से संबन्धित हो जिसकी बाबत विधान सभा को संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (3) के अधीन विधि (कानून) बनाने की शक्ति हो, ऐसा चिकित्सक शामिल होगा, जिसका नाम इस अध्यादेश के अधीन रजिस्ट्रार में प्रविष्ट है ; और

(ii) प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी को, यदि वह चाहे, मृत्यु समीक्षा पर सेवा (सर्विस आन एन इन्कर्वेस्ट) से छूट दी जाएगी।

साधारण
उपबन्ध।

26. इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी चिकित्सा व्यवसायियों को लागू साधारण उपबन्धों से युक्त भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अतिरिक्त है न कि उसके अल्पीकरण में।

रजिस्ट्रीकृत
होने का
मिथ्या दावा
करने के
लिए शास्ति।

27. यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम तत्समय रजिस्ट्रार में दर्ज नहीं है, मिथ्या कहता है कि उसका नाम दर्ज है या यह सुझाव देने के लिए कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है, अपने नाम या शीर्षक या युक्तियुक्त रूप से संगणित किन्हीं अन्य शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता है, वह इस प्रकार सिद्ध दोष पाए जाने पर जुर्माने से दण्डित होगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा।

28. कोई व्यक्ति जो मिथ्या धारणा करता है कि वह इस अध्यादेश की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित चिकित्सा व्यवसायी है तथा चिकित्सा की आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली की चिकित्सा करता है तो वह कठोर कारवास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित होगा।

चिकित्सा व्यवसायी या मिथ्या धारणा अपराध।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के अधीन, इस अध्यादेश की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित चिकित्सा व्यवसायियों या व्यवसायियों (प्रेक्टिशनर) को ही दण्ड दिया जा सकेगा और पशु चिकित्सा या पशु शल्यचिकित्सा या होम्योपैथी अथवा आयुर्वेदिक या सिद्धा या यूनानी पद्धति का व्यवसाय करने वाले को या आयुर्वेद चिकित्सा और शल्यचिकित्सा (बी० ए० एम० एस०) का स्नातक या भारतीय चिकित्सा और शल्यचिकित्सा में उपाधि रखने वालों को कोई भी दण्ड नहीं दिया जा सकेगा।

29. (1) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट से अन्यथा कोई भी न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध का संज्ञान या विचारण नहीं करेगा।

इस अध्यादेश के अधीन अपराध का विचारण तथा अपराध का संज्ञा लेने के लिए सत्र न्यायालय।

(2) कोई भी न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर के सिवाय न करेगा।

30. (1) यदि किसी भी समय सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद् या इसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस अध्यादेश के अधीन या द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रहा है या उनका अतिरेक किया है या दुरुपयोग किया है या कार्य नहीं किया है या कार्य करने में असक्षम रहा है तो सरकार, यदि ऐसी असफलता, अतिरेक, दुरुपयोग या अक्षमता को गम्भीर प्रकृति की समझती है तो वह, यथास्थिति, उसकी विशिष्टियों की सूचना परिषद् या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दे सकेगी।

सरकार का नियन्त्रण।

— (2) यदि यथास्थिति, परिषद् या इसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसी असफलता, दुरुपयोग या अक्षमता को, ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर दूर करने में असफलता रहता है जिसे सरकार इस निमित्त नियत करें, तो सरकार, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा सकेगी या परिषद् को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भंग कर सकेगी और परिषद् के भंग होने की दशा में परिषद् की समस्त या किन्हीं शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग, पालन या निर्वहन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा करवा सकेगी, जिन्हें सरकार इस निमित्त नियुक्त करें:

परन्तु नई परिषद् का गठन, इसके भंग होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व किया जाएगा।

(3) इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस अध्यादेश के अधीन, किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने या किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त परिषद् या अन्य कोई प्राधिकारी का गठन या नियुक्ति विधिमान्यतः नहीं की गई है तो सरकार ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग या पालन ऐसी रीति में और छः मास से अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अध्याधीन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह उचित समझे, करवा सकेगी।

नियम बनाये 31. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस की शक्ति। अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेंगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) वह समय और स्थान जिसमें और जिस रीति में सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इस अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन निर्वाचन किया जाएगा।
- (ख) वह रीति जिसमें इस अध्यादेश की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन, परिषद् की बैठक संयोजित, आयोजित और संचालित की जाएगी ;
- (ग) परिषद् की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य शर्तें जिनका प्रयोग और पालन किया जाएगा तथा इस अध्यादेश की धारा 10 के अनुसार आचार संहिता द्वारा व्यवसायियों के व्यवसायिक आचरण का विनियमन ;
- (घ) निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो कि परिषद् की कार्यकारी समिति का गठन करने के लिए इसके सदस्यों में से परिषद् द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और उनका कार्यकाल और उनमें से आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और परिषद् की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य भी जो इस अध्यादेश की धारा 11 के उपबंधों के अधीन कार्यकारी समिति द्वारा प्रयुक्त किए जाने, पालन किए जाने और निर्वहन किए जाने के लिए परिषद् द्वारा, प्रत्यायोजित किए गए हों।
- (ङ) अध्यादेश की धारा 12 के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद् के अन्य सदस्यों तथा इसकी कार्यकारी समिति के सदस्यों को संदेय भत्ते ;
- (च) रजिस्ट्रार का वेतन व भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें, रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् के लेखों के रख-रखाव की रीति, कर्मचारीवृन्द पर रजिस्ट्रार की पर्यवेक्षी शक्तियां और कर्तव्य तथा कृत्य, जो इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जिनका पालन व निर्वहन रजिस्ट्रार द्वारा किया जा सकेगा ;
- (छ) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द की सेवा शर्तें ;
- (ज) चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर को तैयार करना और रख-रखाव, ऐसे रजिस्टर का प्ररूप, रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के नाम, पते और अर्हताओं आदि सहित विशिष्टियां आवेदन के प्ररूप का निर्धारण नाम रजिस्ट्रीकृत करने हेतु राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला नोटिस, ऐसी प्रविष्टि के लिए संदेय की जाने वाली फीस का निर्धारण और व्यक्तिगत नोटिसों को भेजने के लिए प्ररूप के निर्धारण हेतु संदाय की रीति, इस अध्यादेश की धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्ररूप का निर्धारण ;
- (झ) अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्ररूप का निर्धारण करना ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस और इस अध्यादेश की धारा 18 के अधीन अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के प्ररूप का निर्धारण करना ;
- (ञ) रजिस्टर में नाम परिवर्तन अभिलिखित करने के लिए फीस का निर्धारण ; रजिस्टर में अतिरिक्त अर्हता की प्रविष्टि के लिए संदेय फीस का निर्धारण और इस अध्यादेश की धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रीकरण द्विप्रतिक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संदेय फीस का निर्धारण ;

- (ट) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की सूची का प्ररूप और इस अध्यादेश की धारा 20 के अधीन सूची के प्रकाशन की रीति ;
- (ठ) परिषद् या रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की रीति, रजिस्टर में व्यवसायी के नाम की पुनः प्रविष्टि के लिए शर्तें और इस निमित्त प्रभारित की जाने वाली फीस और अध्यादेश की धारा 22 के अधीन एसेसर (कर-निर्धारक) को संदेय संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक ;
- (ड) नोटिस का प्ररूप और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप, अनुमोदित चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में उपस्थित का साक्ष्य और इस अध्यादेश की धारा 23 के अधीन अनिविनिकरण के कारण रजिस्टर से हटाए गए नाम की पुनः प्रविष्टि के लिए संदेय फीस ;
- (ढ) वह रीति जिसमें इस अध्यादेश की धारा 23 के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध परिषद् द्वारा अपीलों की सुनवाई की जाएगी ;
- (ण) इस अध्यादेश की धारा 29 की उप धारा 2 के अधीन परिवाद करने के लिए सशक्त अधिकारी ; और
- (त) इस अध्यादेश के अधीन विहित किया जाने वाला या किया जा सकने वाला कोई अन्य मामला ।

(3) इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे ,

32. परिषद् भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा यथा विहित आचार संहिता और चिकित्सा सदाचारों का समय-समय पर अनुसरण करेगी ,

आचार
संहिता और
सदाचार ।

सूरज भान,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

सचिव विधि ,

हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला :

तारीख :

AUTHORITATIVE 'ENGLISH TEXT'

H. P. Ordinance No. 3 of 2002.

THE HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL
ORDINANCE, 2002

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-third Year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

to provide for the constitution of Himachal Pradesh Medical Council, and the maintenance of a register of Medical Practitioners who are engaged in the practice of modern scientific system of medicine and all its branches in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith.

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance.—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Medical Council Ordinance, 2002.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) This section shall come into force at once, and the remaining provisions of this Ordinance shall come into force on such date as the Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

- (a) "appointed day" means the date on which the provisions of this Ordinance other than section 1 shall come into force under sub-section (3) of section 1;
- (b) "causal vacancy" means a vacancy occurring otherwise than by efflux of time in any office filled by election or nomination;
- (c) "Council" means the Himachal Pradesh Medical Council constituted under section 3 of this Ordinance;
- (d) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Council constituted under section 11 of this Ordinance;
- (e) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

102 of 1956

102 of 1956

- (f) "medical practitioner" or "Practitioner" means a person who is engaged in the practice of modern scientific system of medicine and all its branches and has qualification as prescribed in the First, Second or Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956;
- (g) "medicine" means the modern scientific system of medicine and includes surgery and obstetric but does not include veterinary medicine or veterinary surgery or the Homoeopathic or the Ayurveda or the Sidha or the Unani system of medicine and the expression "medical" shall be construed accordingly;
- (h) "member" means a member of the Council;
- (i) "Official Gazette" means the Rajptra of Himachal Pradesh;
- (j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance;
- (k) "President" means the President of the Council;
- (l) "Vice-President" means the Vice-President of the Council;
- (m) "register" means the register of medical practioners prepared or deemed to be prepared and maintained under this Ordinance;
- (n) "registered practioner" means a medical practioner having requisite qualification as prescribed in the Indian Medical Council Act, 1956 and whose name is, for the time being entered in the register, but does not include a person whose name is provisionally entered in the register; and
- (o) "Registrar" or "Deputy Registrar" means the Registrar or the Deputy Registrar, as the case may be, appointed under section 14 of this Ordinance;

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF COUNCIL

3. (1) With effect from such date as the Government may, by notification in the Official Gazette notify, there shall be constituted for the purposes of this Ordinance, a Council to be called "The Himachal Pradesh Medical Council".

Constitution and composition of the Council.

(2) The Council shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, whether movable or immovable, and to contract and to do all things necessary for the purposes of this Ordinance, and may by the name aforesaid sue and be sued.

(3) The Council shall consist of the following members, namely:—

- (a) four members having requisite qualification as prescribed in the Indian Medical Council Act, 1956, to be nominated by the Government;
- (b) One member from each Government medical college established by law in Himachal Pradesh having a medical faculty, elected by members of the medical faculty of that college from amongst its permancent members of teaching faculty;

102 of 1956

- (c) nine members to be elected by registered practitioners from amongst themselves including one member elected by the Himachal Pradesh Medical Association :

Provided that no registered practitioner shall be entitled to vote or stand as a Candidate for election, unless,—

- (i) he is a citizen of India;
(ii) he either resides or carries on his profession or is employed in Himachal Pradesh;

- (d) Principal of the Government Medical Colleges in Himachal Pradesh as *ex-officio* member ; and

- (e) Director of Health Services, Himachal Pradesh as *ex-officio* member.

(4) The President and Vice-President shall be elected by the members from amongst themselves.

(5) The election of the members, and of the president and Vice President shall be held at such time, and at such place, and in such manner, as may be prescribed.

(6) If at any election, the electors fail to elect the requisite number of members, or the President or the Vice-President, the Government shall nominate members from amongst persons qualified to be elected as members of the respective category, as it deems fit, to fill in the vacancy or vacancies, and the persons so nominated shall be deemed to have been elected for the period till such time the vacancies are filled in on regular basis under this section.

(7) Where any dispute arises regarding any election of a member or of the President or Vice-President, it shall be referred to the Government, and the decision of the Government shall be final.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (3):—

- (a) in respect of the constitution of the Council for the first time under this Ordinance, the members thereof shall be nominated by the Government from amongst persons qualified to be elected or nominated as member of the respective category ; and
(b) the members so nominated shall hold office for such period not exceeding three years in the aggregate as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

(9) The Government shall, by notification in the Official Gazette, publish the names of the members.

Term of
Office
President,
Vice-Presi-
dent and
members.

4. (1) Save as otherwise provided in this Act, a member, shall hold office for a term of five years from the date of publication of the notification under sub-section (9) of section 3 of this Ordinance :

Provided that where a person is elected by members of medical faculty of a Government medical college, or is an *ex-officio* member, he shall

cease to hold office as a member if he ceases to belong to that faculty, or as the case may be, ceases to hold such office, before the expiry of his term.

(2) Save as otherwise provided in this Ordinance, the President or the Vice-President shall hold office from the date of his election upto the day on which his term of office as member expires.

(3) The term of office of an outgoing member shall, notwithstanding anything contained in sub-section (1) be deemed to extend and to expire with the day immediately preceding the day on which the names of the successor members are published under sub-section (9) of section 3 of this Ordinance.

(4) The term of office of an outgoing President or Vice-President shall, notwithstanding anything contained in sub-section (2), be deemed to extend and to expire on the day immediately preceding the day on which the successor President or Vice-President, as the case may be, is elected.

(5) An outgoing member, President or Vice-President shall be eligible for re-election or renomination for one more consecutive term only.

(6) Leave of absence may be granted by the Council to any member for a period not exceeding six months.

5. (1) A casual vacancy in the office of President or the Vice-President or a member elected under clause (b) or clause (c) of sub-section (3) of section 3, shall be filled by election :

Casual
Vacancy.

Provided that any such vacancy in the office of an elected member occurring within six months prior to the date on which the term of office of all the members expires, shall not be filled.

(2) A casual vacancy in the office of a member nominated under clause (a) of sub-section (3) or under sub-section (8) of section 3 shall be reported forthwith by the Registrar to the Government, and shall as soon as possible thereafter, be filled by the Government, by nomination.

(3) Any person elected under sub-section (1) or nominated under sub-section (2) to fill a casual vacancy shall, notwithstanding anything contained in sub-section (8) of section 3 or section 4 of this Ordinance, hold office only so long as the person in whose place he may be elected or nominated, as the case may be, would have held office, if the vacancy had not occurred.

6. (1) The President or the Vice-President may at any time resign his office by a notice in writing addressed to the Council and delivered to the Registrar and the resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Council or on the expiry or sixty days from the date of the delivery of the notice, whichever event occurs earlier.

Registration.

(2) An elected member may, at any time, resign his office by a notice in writing addressed to the President and a nominated member may at any time resign his office by a notice in writing addressed to the Government



and delivered to the Registrar. Every such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the President or, as the case may be the Government or on the expiry of sixty days from the date of the receipt of the notice, whichever event occurs earlier.

Disquali-
fications.

7. (1) A person shall be disqualified for being elected or nominated as, and for continuing as, a member,—

- (a) if he is an undischarged insolvent; or
- (b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if his name has been removed from the register and has not been re-entered therein; or
- (d) if he is a whole time officer or servant of the Council ; or
- (e) if he has been convicted for an offence involving moral turpitude.

(2) If any member absents himself from three consecutive meetings of the Council, without leave of the Council granted under sub-section (7) of section 4 or without such reasons as may in the opinion of the Council, be sufficient, the Council may declare his seat vacant and take steps to fill the vacancy.

(3) If any member becomes, or is found to be, subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1), the Council shall submit a report to the Government, and the Government, if satisfied about the disqualifications, shall declare his seat vacant.

Meeting
of the
Council.

8. (1) The meetings of the Council shall be convened, held and conducted in such manner as may be prescribed.

(2) The President, when present, shall preside at every meeting of the Council and if at any meeting the President is absent, the Vice-President, and in the absence of both, some other member elected by the members present from amongst themselves, shall preside at such meeting.

(3) All issues at a meeting of the Council shall be decided by a majority of members present and voting.

(4) The presiding authority at a meeting shall have and exercise a second or casting vote, in case of an equality of votes.

(5) Eight members including the President and Vice-President shall form quorum. When a quorum is required but not present, the presiding authority shall, after waiting for not less than thirty minutes for such quorum, adjourn the meeting to such hour or some future day as it may notify on the notice board at the office of the Council, and the business which would have been brought before the original meeting had there been a quorum there at, shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed of at such meeting or any subsequent adjournment thereof, whether there be a quorum present, or not.

Proceeding
of meetings
and Validity
of act.

9. (1) The proceedings of every meeting of the Council, shall be treated as confidential, and no person, shall, without the previous resolution of the Council, disclose any portion thereof :

Provided that nothing in this section shall be deemed to prohibit any person from disclosing or publishing the text of any resolution adopted by the Council, unless the Council directs such resolution also to be treated as confidential.

(2) No disqualification or defect in the election or nomination of any person as a member, or as the President, or as the Vice-President, or as presiding authority of a meeting shall by itself be deemed to vitiate any act or proceedings of the Council in which such person has taken part, if the majority of persons who are parties to such act or proceedings, were entitled to vote.

(3) During any vacancy in the Council, the continuing members may act, as if no vacancy had occurred.

(4) Any act done by the Council shall not be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Council.

10. Subject to such conditions as may be prescribed by or under the provision of this Ordinance, the powers, duties and functions of the Council shall be:—

Powers,
duties and
functions
of the
Council.

- (a) to maintain the live register and to provide for the registration of medical practitioners;
- (b) to hear and decide appeals against any decision of the Registrar;
- (c) to prescribe a code of ethics for regulating the professional conduct of practitioners;
- (d) to reprimand a practitioner, or to suspend or remove his name from the register, or to take such other disciplinary action against him as may, in the opinion of the Council be necessary or expedient;
- (e) to receive complaints from public (including patients or their relatives) against misconduct or negligence by a medical practitioner, to proceed for inquest, take a decision on the merits of the case and to initiate disciplinary action or award compensation and similarly to take action against frivolous complaints;
- (f) to ensure that no unqualified person practices modern scientific system of medicine;
- (g) to exercise such other powers, perform such other duties and discharge such other functions, as may be prescribed; and
- (h) to provide protection to its members in discharging professional duties.

11. (1) The Council shall, as soon as may be, constitute an Executive Committee consisting of the President as *ex-officio* member and such other members, elected by the Council from amongst its members, as may be prescribed.

Executive
Committee.

(2) The term of office and the manner of filling casual vacancies among and the procedure to be followed by the members of the Executive Committee shall be such, as may be prescribed.

(3) In addition to the powers, duties and functions conferred, imposed and entrusted by this Ordinance, the Executive Committee shall exercise such powers, perform such duties, and discharge such functions of the Council, as may be entrusted to it from time to time, by the Council.

(4) The President shall be the *ex-officio* Chairman of the Executive Committee.

Allowances payable to members of the Council and Executive Committee.

12. There shall be paid to the President, the Vice President and other members of the Council and to the members of its Executive Committee, such travelling and other allowances as may be prescribed.

Income and Expenditure of the Council.

13. (1) The Income of the Council shall consist of:—

- (a) registration fees received from the practitioners;
- (b) grants received from the Government, if any; and
- (c) any other sums raised by the Council.

(2) It shall be competent for the Council to incur expenditure for the following purposes, namely:—

- (a) salaries and allowances of the Registrar and the staff appointed by the Council;
- (b) travelling and other allowances paid to the members of the Council and the Executive Committee;
- (c) remuneration paid to the assessors; and
- (d) such other expenses as are necessary for performing the duties and discharging the functions under this Ordinance.

Appointment of Registrar and Deputy Registrar, their duties and functions.

14. (1) The Council shall, with the previous sanction of the Government, appoint a Registrar or a Deputy Registrar who shall be a qualified medical graduate as prescribed in Schedule I, II and III of the Indian Medical Council Act, 1956.

(2) The Executive Committee may grant leave to the Registrar ;

Provided that, if the period of leave does not exceed one month, the leave may be granted by the President.

(3) During the temporary vacancy in the office of the Registrar due to leave or any other reasons, the Deputy Registrar shall act as Registrar and in the absence of Registrar and Deputy Registrar, the Executive Committee may, with the previous sanction of the Government, appoint another person to act in his place and any person so appointed shall for the period of such appointment be deemed to be the Registrar for the purposes of this Ordinance :

Provided that, when the period of such vacancy does not exceed one month, the appointment may be made by the President, who shall forthwith report such appointment to the Executive Committee and the Government.

(4) The Council may, with the previous sanction of the Government, suspend, dismiss or remove any person appointed as the Registrar, or impose any other penalty upon him in the manner as may be prescribed.

(5) Save as otherwise provided in this Ordinance, the salary and allowances and other conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed.

(6) The Registrar shall be the Secretary and the Executive Officer of the Council and he shall attend all meetings of the Council, and of its Executive Committee, and shall keep minutes of the meetings and names of members present and of the proceedings of such meetings.

(7) The accounts of the Council shall be kept by the Registrar, in the prescribed manner.

(8) The Registrar shall have such supervisory powers over the staff as may be prescribed and may perform such other duties and discharge such other functions as may be prescribed.

(9) The Registrar shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

CHAPTER-III

PREPARATION AND MAINTENANCE OF REGISTER

15. (1) As soon as may be after the appointed day, the Registrar shall prepare and maintain a register of Medical practitioners for Himachal Pradesh in accordance with the provisions of this Ordinance.

Preparation of register.

(2) The register shall be in such form, and may be divided into such parts as may be prescribed. The register shall provide for the full name, address and qualifications with the name of College and University of the registered practitioner, the date on which each qualification was obtained and such other particulars as may be prescribed.

(3) Any person who possesses any of the qualifications specified in Schedules I, II, or III to the Indian Medical Council Act, 1956, shall subject to any condition laid down by or under the Indian Medical Council Act, 1956, at any time on an application made in the prescribed form to the Registrar and on payment of a prescribed fee and on presentation of proof of his registerable qualification, be entitled to have his name entered in the register.

(4) Every person, whose name was entered on a date prior to 1st May, 1961, in Indian Medical Council register and continued in such register on the day immediately preceding the appointed day, shall be entitled to have his name continued in the register prepared under this Ordinance.

(5) Within a period of three months from the appointed day or such further period as the Government may allow, the Registrar shall publish a general notice in the Official Gazette and in such news papers, as the Council may select, in such form as may be prescribed, calling upon every

person to whom sub-section (4) applies, to pay to the Registrar in the prescribed manner the prescribed fee if he desires to have his name entered in the register maintained under this Ordinance, and shall also send individual notice for like purpose by registered post to every such person at his last known address in such form as may be prescribed. The name of every such person who pays such fee before the expiry of the period of two months from the date of publication of the general notice in the Official Gazette shall be entered in the register.

(6) After the last date for payment of the prescribed fee under sub-section (5) has expired and the register prepared in accordance with foregoing provisions is ready, the Registrar, shall publish a notice in the Official Gazette and in such news papers as the Council may select, about the register having been prepared, and the register shall come into force from the date of publication of such notice in the Official Gazette.

(7) No person though qualified in modern scientific system of medicine, shall practise in the State of Himachal Pradesh without having a certificate of registration. Any person servicing or practising modern scientific system of medicine in Himachal Pradesh shall be registered with the Council under this Ordinance.

(8) Every registered practitioner shall be given a certificate of registration in the prescribed form. The registered practitioner shall display the certificate of registration in a conspicuous part in the place of his practice and if he has more than one such place, in any one of them, such registration shall be valid for a period of three years.

(9) Any person who contravenes provisions of sub-section (7) shall on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees.

Special
procedure
for regis-
tration in
Certain
cases.

16. (1) No person who possesses a medical qualification granted by any authority in any place outside the territory of India (other than the qualification specified in the IInd or IIIrd Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956, shall be registered under this Ordinance, unless the procedure specified in sub-section (2) has been followed.

(2) Any person, who holds any such medical qualification may apply to the Council for registration by giving a correct description of his qualification, with his degree, diploma, licence or certificate. The Council shall transmit the same to the Medical Council of India for opinion and shall act according to their opinion.

Persons
who may
not be
registered.

17. Notwithstanding anything contained in sections 15 and 16 of this Ordinance, no person whose name has been removed whether before or after the appointed day, from any register kept under this Ordinance or any other law for the time being in force in India regulating the registration of medical practitioners on the ground of professional misconduct, shall be entitled to have his name entered in the register, unless his name is duly ordered to be restored to the register from which it was so removed.

Fee for
provisional
registration.

18. (1) Any person who desires to be registered provisionally under section 25 of the Indian Medical Council Act, 1956, shall make an application to the Registrar and shall pay the prescribed fee.

(2) every person whose name is entered in the register under sub-section (1) shall be given a certificate of provisional registration in the prescribed form and such certificate shall remain in force for such period as may be specified therein.

19. (1) It shall be the duty of the Registrar to make entries in the register, and to issue certificate of registration in accordance with the provisions of this Ordinance, and the rules made thereunder.

Maintenance of register.

(2) Every Registrar of Deaths on receiving notice of the death of a medical practitioner registered under this Ordinance, shall forthwith transmit by post to the Registrar appointed under this Ordinance, a certificate under his own hand of such death with the particulars of time and place of death and may charge the cost of such certificate and transmission, as an expense of his office.

(3) The names of registered practitioners, who die or whose names are directed to be removed from the register under section 22 of this Ordinance, shall be removed therefrom.

(4) Any person whose name is entered in the register and who subsequent to his registration desires to record in the register any change in his name shall, on an application made in this behalf and on payment of prescribed fee be entitled to have such change in his name recorded in the register.

(5) Subject to the provisions of section 26 of the Indian Medical Council Act, 1956, any person whose name is entered in the register and who subsequent to his registration obtains any additional qualification specified in any of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956, shall on an application made in this behalf, and on payment of the prescribed fee, be entitled to have an entry stating such additional qualification made against his name in the register.

(6) Where it is shown to the satisfaction of the Registrar that a certificate of registration has been lost or destroyed, the Registrar may, on payment of prescribed fee and on furnishing an indemnity bond issue a duplicate certificate after due confirmation and approval of the Executive Committee.

20. (1) At such time, after the publication of the notice under sub-section (6) of section 15 of this Ordinance, as the Council deems fit and thereafter every three years, the Registrar shall cause to be printed and published a corrected list of all persons for the time being entered in the register but not later than three months of the start of election process.

Publication of list of registered practitioners.

(2) The Registrar shall cause to be printed and published annually on or before a date to be decided by the Executive Committee, an addendum and a corrigendum to the list published under sub-section (1) showing:—

(a) the names of all persons for the time being entered or re-entered in the register and not included in any subsisting list already printed and published;

- (b) the names of all practitioners included in any subsisting list, whose names have since been removed on account of any reason whatsoever from, and not re-entered in the register; and
- (c) any other amendment to the subsisting list.

(3) The form of the list published under sub-section (1), the particulars to be included therein, and the manner of its publication, shall be such as may be prescribed.

(4) A copy of the list referred to in sub-section (1) shall be conclusive evidence in all courts, and in all judicial or quasi-judicial proceedings, that the persons therein specified are registered according to the provisions of this Ordinance, and the absence of the name of any person from such copy shall be evidence, until the contrary is proved, that such person is not registered according to the provisions of this Ordinance:

Provided that in the case of any person whose name does not appear in such copy a certified copy under the hand of the Registrar of the entry of the name of such person on the register shall be evidence that such person is registered under the provisions of this Ordinance.

Disciplinary
Committee.

21. There shall be a Disciplinary Committee comprising of,—

- (i) a Chairman to be nominated by the Council ;
- (ii) a member of Legislative Assembly of the Himachal Pradesh nominated by the Speaker ;
- (iii) a Legal Expert to be nominated by the Council ;
- (iv) an eminent publicman nominated by the Government ;
- (v) an eminent medical specialist in the relevant speciality to which the complaint pertains, to be nominated by the Council ; and
- (vi) a member nominated by Medical Association of Himachal Pradesh with minimum ten years standing.

Removal of
names from
the register.

22. (1) If a registered practitioner has been, after due inquiry held by the Council or by the Executive Committee in the prescribed manner, found guilty of any misconduct, the Council may,—

- (a) issue a letter of warning to such practitioner ; or
- (b) direct the name of such practitioner—
 - (i) to be removed from the register for such period as may be specified in the aforesaid direction ; or
 - (ii) to be removed from the register permanently.

Explanation.—For the purpose of this section a registered practitioner shall be deemed to be guilty of misconduct if—

- (a) he is convicted by a criminal court for an offence which involves moral turpitude ; or

(b) in the opinion of the Council his conduct is infamous in relation to the medical profession particularly, under any code of ethics prescribed by the Council or by the Medical Council of India constituted under the Indian Medical Council Act, 1956, in this behalf.

(2) The Council may, on sufficient cause being shown, direct on any subsequent date that the name of a practitioner removed under sub-section (1) be re-entered in the register on such conditions, and on payment of such fee, as may be prescribed.

(3) The Council may, of its own motion, or on the application of any person, after proper inquiry and after giving an opportunity to the person concerned of being heard cancel or alter any entry in the register, if in the opinion of the Council, such entry was fraudulently or incorrectly made.

(4) In holding any inquiry under this section, the Council or the Executive Committee, as the case may be, shall have the same powers as are vested in Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

(a) enforcing the attendance of any person, and examining him on oath ;

(b) compelling the production of documents ; and

(c) issuing of commissions for the examination of witnesses.

(5) All the inquiries under this section shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code, 1860.

(6) For the purpose of advising the Council or the Executive Committee as the case may be, on any question of law arising in any inquiry under this section, there may in all such inquiries be an assessor, who has been for not less than ten years.—

(i) an advocate enrolled under the Advocates Act, 1961 ;

or

(ii) an attorney of a High Court.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, in computing the period during which a person has been enrolled as an Advocate, there shall be included any period during which he was enrolled as an Advocate under the Indian Bar Council Act, 1926.

(7) Where an assessor advises the Council, or the Executive Committee, as the case may be, on any question of law as to evidence, procedure or any other matter, he shall do so in the presence of every party or person representing a party to the inquiry who appears thereat or if the advice is tendered after the Council or the Executive Committee has begun to deliberate as to its findings, every such party or person as aforesaid shall be informed what advice the assessor has tendered. Such party or person shall also be informed if, in any case, the Council or the Executive

Committee does not accept the advice of the assessor on any such question as aforesaid.

(8) Any assessor under this section may be appointed either generally, or to any particular inquiry, and shall be paid the prescribed remuneration.

Renewal of
registration.

23. (1) Notwithstanding anything contained in sections 15 and 20 of this Ordinance, on such date, after the date of publication of the notice under sub-section (6) of section 15, as the Executive Committee may, with the previous sanction of the Government, decide, and every three years thereafter, the Registrar shall cause a notice in the prescribed form to be published in the Official Gazette calling upon all registered practitioners to make an application within a period of 45 days from the date of publication of the notice to the Registrar for the continuance of their names on the register together with such proof of having attended approved Medical Education programme as may be prescribed.

(2) If the application is not made on or before the date fixed by the Registrar shall remove the name of the defaulter from the register and shall inform him of such removal by registered post :

Provided that if an application for continuance of the name so removed is made within a period of six months from the date of removed of name from the register the name so removed may be re-entered in the Register on payment of prescribed fee.

Appeals.

24. (1) Any person aggrieved by any decision of the Registrar under this Ordinance may, within a period of thirty days from the date on which the decision is communicated to him, appeal to the Council which shall hear and decide the appeal in the prescribed manner.

(2) Save as otherwise provided in the Indian Medical Council Act, 1956, the decision of the Council under this Ordinance shall be final.

Rights of
registered
practitioner.

25. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force—

(i) the expression “legally qualified medical practitioner” or “duly qualified medical practitioner” or any word importing a person recognised by law as a medical practitioners or member of the medical profession shall in all Acts of the Himachal Pradesh and all the Central Acts (in their application to the State of Himachal Pradesh) in so far as such Acts relate to any matter with respect to which the Legislative Assembly has powers to make laws, under clause (3) of article 239 AA of the Constitution, include a practitioner whose name is entered in the register under this Ordinance ; and

(ii) every registered practitioner shall be exempted if he so desires, from serving on an inquest .

General
provisions.

26. The provisions of this Ordinance are in addition to, and not in derogation of the provisions of the Indian Medical Council Act, 1956

102 of 1956

containing general provisions applicable to all medical practitioners.

27. If any person whose name is not for the time being entered in the register, falsely represents that it is so entered, or uses in connection with his name or title any words or letters reasonably calculated to suggest that his name is so entered, he shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees.

Penalty for falsely claiming to be registered.

28. Any person who falsely assumes that he is a medical practitioner or practitioner as defined in clause (f) of section 2 of this Ordinance and practises the modern scientific system of medicine, shall be punished with rigorous imprisonment which may extend upto three years, or with fine which may extend upto Rs. 20,000, or with both.

False assumption of medical practitioner or practitioner to be an offence.

Explanation.—Under this section, punishment can be awarded only to medical practitioners or practitioner as defined in clause (f) of section 2 of this Ordinance and no punishment may be awarded to any one practising Veterinary medicine or Veterinary surgery or Homoeopathic or the Ayurvedic or the Siddha or the Unnani System of Medicine or those holding Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Bachelor of Indian Medicine and Surgery degree.

29. (1) No court other than the court of the Chief Judicial Magistrate shall take cognizance of, or try an offence, under this Ordinance.

Court competent to try offence under this Ordinance and take cognizance of offence.

(2) No court shall take cognizance of any offence under this Ordinance except on a complaint in writing made by an officer empowered by rules made in this behalf.

30. (1) If at any time it appears to the Government that the Council or the President or Vice-President has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it or him by or under this Ordinance, or has ceased to function or has become incapable of functioning, the Government may, if it considers such failure, excess, abuse or incapacity to be a serious character, notify the particulars thereof to the Council or the President or the Vice-President, as the case may be.

Control of Government.

(2) If the Council or the President, or the Vice-President, as the case may be, fails to remedy such failure, excess, abuse or incapacity within such reasonable time as the Government may fix in this behalf, the Government may remove the President or Vice-President or dissolve the Council for a specified period as the case may be, and in case of dissolution of the Council, cause all or any of the powers, duties and functions of the Council to be exercised, performed and discharged by such registered practitioners or practitioner as the Government may appoint in that behalf;

Provided that a new Council shall be constituted before the expiration of a period of two years from the date of its dissolution.

(3) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, or in the rules made thereunder, if at any time it appears to the Government that the Council or any other authorities empowered to exercise any of the powers or to perform any of the duties or functions under this Ordinance, has not been validly constituted or appointed, the Government may cause any of such powers, duties or functions to be exercised or performed by such person or persons, in such manner and for such period not exceeding six month and subject to such conditions, as it thinks fit.

Power to
make rules.

31. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, and, after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the time and place at which and the manner in which the election of the members and of the President and the Vice-President shall be held under sub-section (5) of section 3 of this Ordinance;
- (b) the manner in which the meeting of the Council shall be convened, held and conducted under sub-section (1) of section 8 of this Ordinance;
- (c) the powers, duties and functions of the Council, the conditions subject to which they shall be exercised and performed; and regulation of professional conduct of practitioners by a code of ethics in accordance with section 10 of this Ordinance;
- (d) number of elected members who shall be elected by the Council from amongst its members for constituting the Executive Committee of the Council; and the term of office of, and the manner of filling casual vacancies among, and the procedure to be followed by the members of the Executive Committee and also the powers and duties and functions of the Council, as may be delegated by the Council to be exercised, performed and discharged by the Executive Committee, under the provisions of section 11 of this Ordinance;
- (e) allowances payable to the President, the Vice-President and other members of the Council, and to the members of its Executive Committee under section 12 of this Ordinance;
- (f) the salary and allowances and other conditions of service of the Registrar, manner of maintenance of the accounts of the Council by the Registrar, supervisory powers of the Registrar over the staff and the duties and functions as may be specified in this Act, which may be performed and discharged by the Registrar;
- (g) the conditions of service of the officers and staff of the Council;
- (h) preparation and maintenance of register of medical practitioners, the form of such register, particulars including the name, address

and qualifications, etc. of the registered practitioners to be entered in the register, prescription of the form of application and of notice to be published in the Official Gazette and news papers to have names registered, prescription of fees to be paid for such entry and the manner of payment of prescription of form for sending individual notices, prescription of the form of certificate which shall be given to registered practitioners under section 15 of this Ordinance;

- (i) prescribing the form of application for provisional registration, fee payable for such registration and prescribing form of certificate of provisional registration under section 18 of this Ordinance ;
- (j) prescription of fee for recording change of name in the register, prescription of the fee payable for entering additional qualification in the register and prescription of fee payable for issue of duplicate certificate of registration under section 19 of of this Ordinance;
- (k) the form of the list of registered medical practitioners and manner of the publication of the list under section 20 of this Ordinance;
- (l) manner for taking disciplinary action etc., against registered practitioners by the Council or by the Executive Committee, conditions for re-entering the name of a practitioner in the register and fee to be charged in this behalf; behalf ; and the remuneration to be paid to an assessor, under section 22 of this Ordinance;
- (m) form of notice and form of application for renewal of registration by registered medical practitioners, proof of having attended approved Medical Education Programme and fee payable for re-entry of name which is removed from the register due to non-renewal under section 23 of this Ordinance;
- (n) the manner in which appeals against the decision of the Registrar shall be heard by the Council under section 24 of this Ordinance;
- (o) Officers who are empowered to make a complaint under subsection (2) of section 29 of this Ordinance; and
- (p) any other matter which is to be, or may be, prescribed under this Ordinance.

(3) All rules made under this Act shall be laid before the Legislative Assembly as soon as may be after they are made.

32. The Council shall follow the code of conduct and medical ethics as prescribed by the Medical Council of India from time to time.

Code of
conduct
and ethics

